

प्रेषक,

डा० एम० सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

संवा में

आध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि०।
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादून: दिनांक: १८ जनवरी, 2005

विषय:- ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या: 853/L/2004-06(1)/23/03, दिनांक 28 दिसम्बर, 2004 द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004-05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष ₹० ४,५३,०७,१००/- (₹० घार करोड़ तिरपन लाख सात हजार एक सौ मात्र) की धनराशि रखीकृत की गई थी।

उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2004 में लेखाशीर्षक के पैरा 17-के स्थान पर अब निम्नवत् पैरा पढ़े जाने की एलद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

17- 'रखीकृत की जा रही धनराशि का व्यव चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ६८०१-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-०५-पारेण एवं वितरण-आयोजनागत-१९०-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मा व अन्य उपकर्मों में निवेश-आयोजनागत-००-०४-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर०इ०सी० से ऋण-(०१०४ से स्थानान्तरित)-३०-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।'

उक्त शासनादेश केवल इस सीमा तक ही संशोधित समझा जाय तथा इसकी शेष सभी शर्ते पूर्ववत् रहेंगी।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 2293'क/वि०अनु०-३/2004, दिनांक 12 जनवरी, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

मददीय,

(१)

(डा० एम० सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या: २०१
/I/200५-06(1)/23/03, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तरांचल।
- 2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मंख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 4- जिलाधिकारी, देहरादून, अल्मोड़ा, बागेश्वर, टिहरी, पौड़ी।
- 5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
- 7- सचिव, नियोजन विभाग।
- 8- वित्त अनुभाग-३
- 9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 10-गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,


(डॉ एन०सी० जोशी)
अपर सचिव